

संभवतः 40 फीसदी है, जब कि राष्ट्रीय औसत 52 प्रतिशत है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस दृष्टि में राजस्थान राज्य ने अपने सम्पूर्ण बजट का 20 प्रतिशत भाग, यानी लगभग एक हजार करोड़ रुपया शिक्षा के लिये इधर-मार्क किया है और वहाँ पर अभी एक नई योजना प्रारम्भ की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मां-बाप के बच्चों को निःशुल्क, मुग्न में किताबें दी जायेंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ऐसे उत्तरी भारत के राज्यों की शिक्षा के विकास की दृष्टि से, जो राज्य सरकारें अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायेंगी, उसमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेंगी?

श्री (ब) भाग में प्रश्न का यह है कि आपने भाग "क" के उत्तर में संख्या नहीं बताई है, उसे बताने की कृपा करें? आपका उत्तर अशुद्ध है, आपने केवल प्रतिशत बताया है, सम्पूर्ण संख्या नहीं बताई है,

So far as part two of the question is concerned. Sir, you kindly verify this fact.

KUMARI SELJA: Sir, only absolute numbers can be supplied

MR. CHAIRMAN: They can be supplied. She will send it to you later. All right?

SHRI SATISH AGARWAL: What about the first part of the question? Will the Central Government come to the assistance of the States in the northern region, where the literacy percentage is below the national average, for providing financial assistance to those States in the northern sector which are providing free text-books to the poor children in the rural areas? Will you come to their aid?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman has come to her aid!

MR. CHAIRMAN: That is the best answer!

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात और महाराष्ट्र में लघु सिंचाई योजनाएँ

*565. श्री जयन्तराम देवर्माकर दबे : क्या जल संसाधन मंत्री यह जनाने की कृपा करेग कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "धारा" "जीवन धारा" और लघु सिंचाई योजनाएँ शुरू करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है,

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गुजरात और महाराष्ट्र को पर्याप्त धनराशि प्रदान की थी ;

(ग) यदि हाँ तो नत्संबंधी ब्यौर क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बिजावरम कुर्ले) : (क) गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों द्वारा धारा के नाम से कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। मिलियन बैल्स योजना जो जवाहर योजना की एक उप योजना है, जीवन धारा के नाम से जानी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को लघु सिंचाई और मिलियन बैल्स योजना के लिए आवंटित की गयी निधियां निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए)

	लघु सिंचाई के लिए	मिलियन बैल्ट योजना के लिए
गुजरात	100.00	29.84
महाराष्ट्र	226.44	88.63

(ख) और (ग) केंद्रीय सरकार ने नव तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई विकास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र

को पर्याप्त निधियां प्रदान की हैं। इनका व्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रुपए)

	1991-92		1992-93		1993-94	
लघु सिंचाई	मिलियन बैल्ट*	लघु सिंचाई	मिलियन बैल्ट*	लघु सिंचाई	मिलियन बैल्ट*	
	योजना		योजना		योजना	
(वास्तविक व्यय)	(आवंटित)	(वास्तविक व्यय)	(आवंटित)	(संशोधित)	(परिवर्धित)	(आवंटित)
गुजरात	30.21	16.18	45.61	22.70	44.02	27.11
महाराष्ट्र	111.96	40.85	203.98	42.67	180.37	80.52

*मिलियन बैल्ट योजना के सामने दी गई राशि में 80 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।